

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग:1

देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2012

विषय : मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु
आबद्धता समाप्त किया जाना।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0-107 /XXXVI(1)/2012-75/2007-टी0सी0 दिनांक
24-05-2012 तथा शासनादेश सं0 151 /XXXVI(1)/2012-75/2007-टी0सी0 दिनांक
20-06-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा मा0
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री मुस्ताक अली
खान व सुश्री सीमा कुमारी को क्रमशः वादधारक (सिविल) एवं वादधारक के पद पर आबद्ध
किया गया था।

2- उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि वह एक व्यवसायिक आबन्धन
है किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है। आबन्धन को उत्तराखण्ड शासन द्वारा किसी भी
समय बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

3- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री
मुस्ताक अली खान व सुश्री सीमा कुमारी की उक्त वादधारक (सिविल) एवं वादधारक के पद
के आबन्धन को एतदत द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या- 196 /XXXVI(1)/2012-75/2007-टी0सी0 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

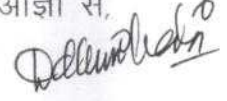
- 1- मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफीसर/निजी सचिव।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 4- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

क्रमशः.....2

(Handwritten signature)

- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 8- सम्बन्धित अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 9- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,



(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव